[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

व्यर्थ हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक बलूच पर्वतीय क्षेत्र में परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। पोखरण और फिर बलूच पर्वतीय क्षेत्र में किए गए परमाणु परीक्षणों से तनाव और विवाद और बढ़ गया है। यह छद्म युद्ध की नहीं बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध की तैयारी है। भारत-पाक सहित पूरा उप-महाद्वीप एक युद्ध क्षेत्र बन गया है और युद्ध सामग्री की तैयारी जारी है। यह इस उपमहाद्वीप में रहने वाली मानवजाति के लिए हितकर नहीं है।

कल मैंने माननीय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण सुना था। वह राष्ट्रीय आस्मिता की रक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर एक बहुत अच्छा भाषण था।

हम एक हैं। हम भारत की सम्प्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थक हैं। निश्चय ही हम एक हैं।

मैं एक साधारण सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। भावना का होना अच्छा है पर विवेक उससे बेहतर है। देशभक्ति और देशप्रेम अच्छे गुण हैं किन्तु विश्वशांति और मानव मात्र के प्रति प्रेम इनसे भी बेहतर है।

आपकी अनुमति से मैं एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ : पोखरण प्रकरण का आप क्या निष्कर्ष है? इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि भारत अब एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, ने दावा किया है कि भारत अब परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह का छठा सदस्य बन सकता है। आज पाकिस्तान भी यह दावा कर सकता है कि वह उक्त समूह का सातवाँ सदस्य बन सकता है। यह तो शस्त्रों की होड़ है जो निरंतर जारी है।

आपकी अनुमति से मैं एक महान व्यक्ति और बांग्ला साहित्य में विख्यात कलकत्ता के महान कवि अन्नदा शंकरराय का एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह को आत्मघाती समूह कहा है और यह अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है आत्मघाती समूह फ्रांस में हुआ करता था जहां जागीरदार और अभिजात्य वर्ग के लोग उल्लासपूर्वक हँस-हँसकर प्राण गँवाया करते थे जो उनका परमानन्द था। आज परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भी अपनी जनता की कीमत पर ऐसे ही आत्मघाती समूह में सम्मिलित हो रहे हैं।

महोदय, परमाणु परीक्षणों की तैयारी करने या परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह में सम्मिलित होने से भारत की गौरवमयी परम्परा और संस्कृति में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह तो गुटनिरपेक्षता और परमाणु निरस्त्रीकरण के सिद्धान्तों का पूर्ण उल्लंघन है। यही हमारा विचार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विचार है कि केवल परमाणु अस्त्र शस्त्रों से ही देश को संकट से नहीं बचाया जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन से क्या संकेत मिलता है? वह तो एक विशाल देश था; वह एक परमाणु शक्ति सम्पन्न देश था। उसका विघटन क्यों हुआ? उसके शस्त्रागार में कई परमाणु अस्त्रशस्त्र होने के बावजूद उसका विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ के विघटन से स्पष्ट होता है कि वहां सरकार की परमाणु नीति के साथ जनता की कोई सहमति नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्यतः कौन से घटक उत्तरदायी हैं? क्या कोई व्यक्ति रिवाल्वर के साथ सुरक्षित रह सकता है? यदि एक व्यक्ति तकिये के नीचे रिवाल्वर रखकर सोता है तो क्या यह उसकी अच्छी स्थिति को दर्शाता है? आग्नेय अस्त्रों के राज में तकिये के नीचे रिवाल्वर रखकर सोने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। मेरा यही विचार है कि जनता की आर्थिक सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असम्भव है।

परमाणु परीक्षण कराने के लिए व्यर्थ गंवाई जाने वाली धनराशि का देश की आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, निवेश उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा ही किसी देश और उसकी जनता को पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तभी उठेगा.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : ठीक है, महोदय।

मई, 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक सफल परीक्षण किया गया था। वह एक उत्कृष्ट परीक्षण था जिसे देश की सम्प्रभुता की रक्षा के नाम पर किया गया था। किन्तु एक वर्ष बाद 25 जून, 1975 को देश को आन्तरिक समस्याओं से बचाने के लिए श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। वह परीक्षण आपातकाल की घोषणा की एक तैयारी रहा। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से यह पूछ सकता हूँ कि क्या पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण व्यवस्था परिवर्तन की कोई तैयारी है?

आज सरकार की संसदीय प्रणाली का राष्ट्रपतीय प्रणाली में बदलने की काफी चर्चा देश में चल रही है। इससे क्या संकेत मिलता है? यह वैसी तैयारी नहीं होनी चाहिए। यही अपेक्षा है। कृपया सावधान रहें।

अतः अब मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखी जा सकती है। आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पोखरण के बारे में लम्बी चर्चा समाप्त होने जा रही है। इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। सारा सदन इस सम्बन्ध में एकमत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, तकनीशियनों ने और सेना के जवानों ने पोखरण के परीक्षण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं।

इस सवाल पर भी लगभग एक राय है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया गया, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को सीमित करने की कोशिश की गई और जो विश्व संस्थाओं से सहयोग हमें अभी तक मिलता था, उसको रोकने का प्रयास हुआ, तो देश पर जितनी भी मुसीबतें आएंगी सारा देश मिलकर उनका सामना करेगा।

स्वाभाविक रूप से इस चर्चा में यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि आखिर पोखरण में परीक्षण की आवश्यकता क्या थी? एक बात मुझे याद आ रही है जब परमाणु 'प्रथम' पर चर्चा हुई थी 1974 में, तो उस समय मैं चर्चा में उपस्थित था, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त भी उपस्थित थे और संसद में दो ही सदस्य हैं जो उस समय भी उपस्थित थे, आज सदन में मौजूद हैं।

उस समय मैंने जो बातें कहीं और आज जो बातें कहने जा रहा हूँ, उनमें कोई अन्तर नहीं है। 1974 में इंदिरा जी ने परीक्षण की इज़ाजत दी थी, सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। उनका निर्णय कोई सामूहिक निर्णय नहीं था, उनका निर्णय प्रतिपक्ष से विचार-विनिमय करने के बाद किया गया हो, ऐसा निर्णय नहीं था लेकिन निर्णय सही था, देश की रक्षा के लिए था। हमारे वैज्ञानिकों को एक आवश्यक अवसर देने की दृष्टि से था, इसलिए उसका स्वागत हुआ। मुझे याद है, जो चर्चा हुई थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाषण नहीं दिया था। उनकी ओर से, सरकार की ओर से, किसी एक और मंत्री ने भाषण दिया था। सारे देश में संतोष था। अभी पड़ोस से इशारा हुआ है कि 1974 में हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे लेकिन अब हम तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत ने परीक्षण किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने परीक्षण किया। क्या सोलह दिन के भीतर परमाणु परीक्षण संभव है? यहां परमाणु परीक्षण से परिचित लोग भी बैठे हैं, जानकार उपस्थित हैं, पन्द्रह दिन के भीतर कोई देश परमाणु परीक्षण की तैयारी नहीं कर सकता। यह तैयारी वर्षों से चल रही थी। कल परीक्षण हुआ, आज खबर आई है कि उन्होंने दूरमार करने वाली कोई मिसाइल आकाश में भेजी है। यह सिलसिला कब से चल रहा है, हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है और देश को तैयार करने का काम भी उन्होंने किया। मैंने एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा था, आज मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ कि इसके पीछे पचास साल का अन्वेषण, अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गर्म बालू में, पचास के करीब टेम्प्रेचर में जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होनी चाहिए।

देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस भावना को लेकर सदन में कोई मतभेद है। हम सबकी भावना है और इस देश की विशेषता रही है कि जब-जब संकट आता है, तो देश सारे मतभेद भुला देता है - लोकतन्त्रवादी देश है, मतभेद होना स्वाभाविक है - "मुण्डे-मुण्डे मत भिन्नः।"

अभी की बात नहीं है, मैं देख रहा था कि 1985 में - शायद किसी ने श्री राजीव गांधी के वक्तव्य को उद्धृत किया है - 11 अक्टूबर को दिल्ली के प्रैस क्लब में एक प्रैस कान्फ्रैंस में श्री राजीव गांधी ने जो कुछ कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ -

[अनुवाद]

"जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है, हमें अपनी सुरक्षा पर विचार करना है और इस मामले में हम नई दिल्ली या भारत के किसी भी अन्य शहर को उपेक्षित होने दें इसका सवाल ही नहीं उठता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कार्यक्रम के बारे में और भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसके लिए अवश्य ही दूसरे देशों से प्राप्त हुआ है। अब हमें चिंता है कि जब कभी परमाणु शस्त्रास्त्र विकसित होंगे तो वे भी इन्हीं देशों के पास जाएंगे। मैंने यह नहीं कहा कि हम आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। पाकिस्तान द्वारा परीक्षण करने के संदर्भ में मैंने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने हैं। हम अपने परमाणु शस्त्रास्त्र बनाएं इसके अलावा भी कई उपाय मौजूद हैं।"

[हिन्दी]

यह उनका 1985 में दिया गया प्रैस कान्फ्रेंस का वक्तव्य है। सरकार के मन में चिंता थी और सीमा के पार क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी थी। इसीलिए जब सवाल आया कि विश्व की महाशक्तियां, जिन्होंने अणु अस्त्रों के अम्बार लगा रखे हैं, इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे अणु अस्त्रों के विनष्ट करने के लिए स्वीकृति दे। वे भेदभावपूर्ण संधि को दुनिया पर लादना चाहते हैं, तो सबने मिल कर फैसला किया, इकट्ठे फैसला किया कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डर था कि हम अलग-थलग पड़ जायेंगे। कभी-कभी अलग-थलग पड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन फैसला सही होना चाहिए और हम अलग-थलग हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विकल्प हमने खुला रखा। लेकिन बाद में जो समाचार प्राप्त हुए, उनसे ऐसा लगा कि इस संबंध में कुछ कहना आवश्यक होगा। वैज्ञानिकों की भी सलाह ली गई कि कौन से कदम उठाए जायें। हमारे लिए अणु अस्त्र विनाश के अस्त्र हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ है, उनका लाभ रक्षा में हैं, आत्म-रक्षा में है। हमारे विरोधी जान लें कि हमारे पास अणु अस्त्र है और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, होगी।

50 साल में तीनबार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देने वाला यह देश है। इसने कभी किसी की भूमि नहीं चाही, इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि यह आक्रमण का शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़नी पड़ी। हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वह बातचीत के द्वारा ही संभव है। लेकिन सौ करोड़ का यह देश इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता है कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करें।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हम शांति के पुजारी हैं, हमें न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए। पारस्परिक हितों का संवर्धन करने वाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ौसी देशों की तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर गुजराल डॉक्टरीन का निचोड़ तो यही था, लेकिन इसे स्वीकार करने में गुजराल साहब को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है उनकी डॉक्टरीन नहीं चली। पाकिस्तान ने नहीं चलने दी। देश के भीतर आतंकवादियों का प्रवेश, सीमा पर संकट बना रहा। बातचीत चल रही थी और मैं इस अवसर पर उस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हूँ - हम पाकिस्तान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है, इसलिए मतभेद के प्रश्नों को हमें आपस में बैठ कर हल करना चाहिए, जो प्रस्ताव ढाका में वार्ता के लिए मंजूर हुए थे, जो सहमति बनी थी उस सहमित पर पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फिर यह प्रस्ताव दोहराया है कि वह भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है - बड़ी अच्छी बात है, वार्ता होनी चाहिए।

मुझे याद है, मैंने एक बार पाकिस्तानी राजनेता से कहा था कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हम और आप पड़ोसी हैं, यह तथ्य कैसे बदला जाएगा। मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं छूट सकता, भूगोल तो हमें बांधे हुए है। मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, वे मैत्री संबंधों का विकास करते हैं और लौटने के बाद यहा आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में असुरक्षा की भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है, ऐसी भावना होने का कोई कारण नहीं है। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया। वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, सम्पन्न रहें, हमें शांति से रहने दें और हम दोनों मिल कर इस भूखंड से ही क्यों सारे संसार से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा के निराकरण के लिए प्रयास करें।

इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम है, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है जिसमें अणु-अस्त्र नहीं होंगे। भारत को निर्णय क्यों करना पड़ा ? क्या हम फिर बेखबर हो जाते ? कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ है, उस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। हम जानते थे यह हो रहा है और इसी की रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया है। मगर इसकी इस तरह से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया है कि आप पहले परीक्षण कर चुके हैं तो वे क्या तैयारी कर रहे थे ?

हमारे लिए तो और भी संकट है। उनके लिए तो अकेले हम हैं। उनके अणु-परीक्षण हमारे खिलाफ है - केवल भारत के विरुद्ध। हम जब अणु परीक्षण करते हैं और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महा-देशों को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिये। एक साथ नहीं कर सकते हैं तो चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत करिये। तब फिर कहा जाता है कि यह रवैया ईमानदारी से नहीं अपनाया जा रहा है। ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस मांग में शामिल हो। अणु-अस्त्रों को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाये जा सकते हैं। लेकिन हमारे अणु-परीक्षण को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है और कहीं समर्थन व्यक्त है और कहीं अव्यक्त है, उससे लगता है कि विश्व का बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थाई शांति चाहता है। ऐसी शांति चाहता है जो अणु-अस्त्रों के कारण खंडित न हो, जिससे शांति विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अपने घर को सुरक्षित रखकर अदा करना चाहते हैं हम अपने घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, दोनों में फर्क नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने और हम हवन करने जाएं और हाथ जला लें, ऐसी स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते हैं और कोई नहीं चाहेगा।

श्री देवेगौड़ा जी यहां नहीं हैं। .....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : हैं, पीछे बैठे हुए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उनके जनता दल का 1996 का मैनीफेस्टो देख रहा हूँ। शायन मैं जिस जनता दल का नाम ले रहा हूँ उससे देवेगौड़ा जी संबंधित हैं।

[अनुवाद]

''हम पाकिस्तान के विरुद्ध परमाणु क्षमता का पहले प्रयोग न करने के लिए औपचारिक रूप से वचन देते हैं।''

[हिन्दी]

हम यह गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी आणविक क्षमता का पाकिस्तान के विरूद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में आवश्यकता हुई तो करेंगे। मगर प्रयोग करने के लिए आपको अणु-क्षमता का विकास करना होगा।

यह भी इस तर्क की पुष्टि करने वाली उक्ति है कि राजनीतिक दलों में इस सम्बन्ध में एक व्यापक राय रही है, एक आम राय रही है। इसे कब किया जाए ? कल जो कुछ हुआ, उसके बाद यहां ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। यह निर्णय किस ने किया, कौन करेगा ? यह आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे बड़े-बड़े सहयोगी जब यह कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो इसमें यह भाव प्रकट नहीं होता कि उन पर मुझे विश्वास नहीं था। इसलिए यह भाव ग्रहण करना कि आम सहमति की बात करते हैं, सलाह नहीं की, उस क्षण जब परीक्षण होना था, सलाह करना संभव नहीं था। इसकी बहुत सीमित लोगों को जानकारी थी। जैसा कल आडवाणी जी ने कहा कि जहां हर चीज लीक हो जाती है, कमीशन की रिपोर्टें पूरी की पूरी प्रकाशित हो जाती हैं, वहां कोई इसका पता नहीं लगा

सका। विदेशों में इसको लेकर काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही है। यह भी राष्ट्र की शक्ति का एक परिचायक है। अगर हम चाहें, परिस्थिति का तकाजा हो और देश के सामने संकटों की चुनौती हो तो इस देश के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, बड़ी से बड़ी सावधानी बरतने के लिए तैयार हैं। यह एक उपलब्धि है। इसका समादर होना चाहिए।

मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब ये आरोप लगाए गए कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह काम किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराना चाहता हूँ। मैं 40 साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती रही है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया, देश के व्यापक स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूँ या बैठा दिया गया हूँ तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ की बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूंगा। यह गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा। भगवान मुझे ऐसा पाप कभी न करने दे। कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई फैसला किस समय किया जाए, किस समय न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती हैं लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। यह 1974 में क्यों किया गया था, हमने ऐसा नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा क्योंकि वह एक ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और इन्दिरा जी उसे उठा सकती थी। बंगलादेश के निर्माण के समय, बंगलादेश की मुक्ति के समय, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इन्दिरा जी का सम्मान किया। हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें सारा देश शामिल था। इसके बाद चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया। हमने इसकी आलोचना नहीं की। हमने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इन्दिरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मेरे शब्द थे युग परिवर्तनकारी काम किया है। अगर हम चुनाव हारेंगे तो हार जाएंगे। चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। सरकारें बनती हैं, बदलती हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकारें बनती हैं, बदलती हैं मगर देश एक रहे, यह देश गर्व के साथ संपन्न हो, यह देश अपनी अनमोल आजादी को बचा सके - यह केवल एक पार्टी का काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है। पोखरन में मैंने अपने भाषण में, शुरू में यह कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, न पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया, देशहित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब यह सवाल उठाया गया कि आपने अपने नेशनल एजेण्डा में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार काम नहीं किया। आज हमारे नेशनल ऐजेण्डा की काफी चिंता की जा रही है। हम इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर नजर रखने वाले लोग हैं, यह जानकार हमें खुशी हुई है लेकिन उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग-अलग हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वह कहेंगे कि ऐसा छपा है तो मैं कहूँगा कि वह ठीक नहीं छपा है। उसमें तीन मुद्दे हैं - सशस्त्र बलों को सुधारना।

[अनुवाद]

"सशस्त्र सेनाओं की तैयारी, मनोबल और युद्ध सम्बंधी प्रभावोत्पादकता की स्थिति पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा और उचित निवारक कार्रवाई की जाएगी।"

[हिन्दी]

इसके बाद के वाक्य में कहा गया है कि -

[अनुवाद]

"हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करेंगे।"

[हिन्दी]

और उसका विवरण दिया गया है। अंत में यह कहा गया है, सचमुच में वह पैरा अलग होना चाहिए था, तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

"उस उद्देश्य से हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु अस्त्र तैनात करने का विकल्प अपनाएंगे।"

[हिन्दी]

यह भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्यूरिटी काउंसिल बना ली जाएगी और सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा होगा तो कल करो तो भी हम यह कहेंगे कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी सेनाएं सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्यूरिटी काउंसिल का निर्माण हुआ है - कोई भी यह अर्थ नहीं निकाल सकता। लेकिन यह अर्थ निकालने का प्रयास हुआ। हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार-विनिमय संभव था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह की मुलाकातें उनकी आयोजित की गई, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो। हम बंगलादेश की लड़ाई लड़े, हम चीन से युद्ध में फंसे थे, हमने पोखरन में परीक्षण भी किया था, यह किया तो कोई अहसान नहीं किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक श्री चिदम्बरम हमारे राजनीतिक चिदम्बरम साहब को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका यह नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। मैं उन सबके बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। हमने कुछ फैसले किये जिनका आंशिक रूप से उल्लेख हो चुका है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा भारत के औचित्यपूर्ण सुरक्षा मामलों को न समझ पाने के कारण हमें निराशा हुई है। मैं उत्तरदायित्वपूर्ण

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बातचीत के लिए सभी प्रमुख पक्षों को साथ लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हम चर्चा करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं।

11 मई के बाद से सरकार ने कुछ कार्यों की पहल की है जिनका मैं यहां वर्णन कर रहा हूँ।

1. हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर पहले ही ऐच्छिक रोक लगा चुके हैं और इसे कानूनी प्रतिबद्धता में बदलने पर विचार और चर्चा के लिए तैयार हैं।
2. हमने 'ए.एफ.एम.सी.टी.' पर वार्ता की पेशकश की है।
3. भारत परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र सम्बंधी प्रौद्योगिकी और जन संहार के शस्त्रास्त्रों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कठोर नियंत्रण लागू करेगा।

हमने पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ 'प्रथम प्रयोग न करने' के समझौते पर चर्चा के प्रस्ताव की घोषणा पहले ही की थी और इसे फिर दोहराते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति चीन के साथ मित्रता के संबंध रखने की है। चीन हमारा पड़ोसी है, दोनों देश एशिया के देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों में परस्पर मित्रता हो और पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे व्यवहार करें, इस बात की आवश्यकता है। सीमा को लेकर कुछ चिंता की बातें जरूर हैं। सीमा पर शांति है। हम बातचीत के द्वारा सीमा का प्रश्न हल करना चाहते हैं। बातचीत जारी है, उसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए और सीमा का एक संतोषजनक हल निकालने का प्रयास होना चाहिए। चीन पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता देता है, उससे भी चिंता पैदा होती है। क्योंकि वह सहायता हमारे विरूद्ध काम में आती हैं। हमारी चिंताओं का भी चीन ध्यान रखे, इस बात की जरूरत है। भारत और चीन मिलकर काम करें, सहयोग से आगे बढ़ें, यह दोनों देशों के ही हित में नहीं है, एशिया के हित में हैं, सारी दुनिया के हित में है। कुछ वक्तव्यों को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी। कठिनाई यह है कि अगर वक्तव्य गलत रूप में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वक्तव्य है वह उचित स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार है वह सुर्खियां प्राप्त कर लेता है। हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखण्ड में शांति बनाये रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जो आज हमारे आलोचक हैं, उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आयेगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद पोखरन गया था, वहां रेडियोधर्मिता भी नहीं थी, हम वहां कई घंटे थे। यह खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है, किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, यह बताने वाला कोई नहीं था। मगर ये खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं।

रेडिया धर्मिता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका हम राजनैतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। सबके सहयोग से आम सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है, उस दायित्व को मैं ऐसी जिम्मेदारी समझता हूँ जिसके निर्वाह के सामने और सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। अब व्यक्ति का, परिवार का, दल का, बिरादरी का और मजहब का सवाल नहीं है। यह देश बहुधर्मी है।

मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, कल हमारे पड़ौसी देश के प्रधान मंत्री ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए किस तरह भड़काने वाला भाषण दिया। वे अपनी जनता को उभाड़ रहे थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पड़ोस में भी करोड़ों लोग रहते हैं। उसमें इस्लाम को मानने वाले भी करोड़ों लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं। समान अधिकार का उपभोग करने वाले हैं। अब एक जुनून पैदा करने की कोशिश की गई। यह एक तरफ तो हम इतने सजग हैं, सतर्क हैं, लेकिन जब सामाजिक सुधारों की यहां पर चर्चा होती हैं, मीडिया में उसकी चर्चा होती है ओर वे अपने देश में उन बातों की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया जनता में ठीक नहीं हो रही है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर मैं देश की जनता को भड़काने लगूं, ऐसा कभी नहीं होगा, और जिस दिन यह करने की नौबत आएगी, उस दिन मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

देश की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। वह समय ठीक प्रकार से देश की सेवा में लगे और इसमें सबका सहयोग मिले, यही मेरे हृदय की कामना है।

पोखरन-एक का मेरा भाषण उद्धृत करते हुए किसी ने कहा था - उसमें मैंने कहा था कि वैज्ञानिकों और सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब राजनेताओं को अपना काम करना है - तो राजनेता से केवल मेरा मतलब नहीं है। राजनेताओं से मतलब सब लोगों से है। हम हम अपने दायित्व का पालन करें, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सुझाव रखा है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध न करने के समझौते पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपका क्या विचार है? क्या आप इस पर एक निश्चित राय कायम करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा करने को तैयार हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जब-कभी बातचीत हुई, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे युद्ध न करने का समझौता चाहते हैं पर तभी जब उनकी इच्छानुसार कश्मीर समस्या का समाधान किया जाए। परंतु अगर कोई नया प्रस्ताव किया गया है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं।

श्री शरद पवार : सुझाव कल ही दिया गया था।

श्री के. नटवर सिंह : क्या मैं प्रधानमंत्री जी से सादर यह पूछ सकता हूँ कि राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखा गया उनका पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में कैसे छप गया ? उस बेहूदा पत्र का मसौदा किसने बनाया था ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे सकता।

रात्रि 8.15 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 1 जून, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 जून, 1998/11 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।